औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था

1580. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की नीति के अन्तर्गत 30.00 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश से स्थापित किये जाने वाले आठ विकास केन्द्रों (औद्योगिक विकास संवृद्धि केन्द्र) को वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा देय अंशदान और ऋण धनराशि दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश की क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात् औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा इस प्रयोजन से आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ;

(ङ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ;

(च) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ; और

(छ) क्या उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और मध्य प्रदेश में अतिरिक्त विकास केन्द्र स्वीकृत करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) मध्य प्रदेश को 6 विकास केन्द्र आवंटित किये गये हैं । वित्तीय संस्थाओं ने अब तक अपना हिस्सा जारी नहीं किया है ।

(ख) निधियां जारी करने पर केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(ग) मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ने अपने चार केन्द्रों को वित्त जारी करने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को आवेदन प्रस्तुत किये हैं ।

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आवेदनों की जांच कर रहा है ।

(ङ) और (च) केन्द्रीय संस्थाओं को योजना के अधीन अपना हिस्सा जारी करने के लिये कहा गया है ।

(छ) योजना के कार्यान्वयन की निरन्तर समीक्षा की जाती है और मध्य प्रदेश राज्य को आबंटित किये गये विकास केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

Discontinuation of subsidy given to *the* indusiries in Gujarat

1581. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have discontinued the subsidy being given to the industrial units in Gujarat State;

(b) if so, the number of such units which are facing crisis in the State;

(c) whether there has been any demand from industrial units in the State to restore the subsidy; and

(d) if so, the steps taken by Government to solve the problem being faced by these units in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Government of India introduced the Central Investment Subsidy Scheme in 1971, and was progressively extended, last upto 30.9.1988, which was applicable to industries in backward areas of all States including Gujarat. Thereafter, the Scheme was not further extended.

(b) The Government has no such information.